

सबके लिए आवास अभियान (Housing Campaign For Everyone – Economy)

- केंद्र सरकार ने सबके लिए आवास योजना हेतु 9 राज्यों में 305 शहरों और कस्बों का चिह्नंकित किया है।
- केंद्र सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास मिशन (दूतमंडल) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की है।
- इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार ने 2022 तक, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाने का निर्णय लिया है।
- इसके चार प्रमुख घटक हैं-
 - § झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास
 - § किफायती आवास
 - § क्रेडिट (साख) लिंकड (मिला हुआ) ब्याज सब्सिडी (सरकार द्वारा आर्थिक सहायता)
 - § लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास-निर्माण के लिए सब्सिडी (सरकार द्वारा आर्थिक सहायता)।
- ये मकान किराए पर नहीं दिए जाएंगे। लाभार्थी को मालिकाना हक मिलेगा।
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।